

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 10783(भ)अनु० दिनांक 03.11.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 121 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों की माह अक्टूबर, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 121 योजनाओं में से 20 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 22 कार्य प्रगति में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 23 योजनाएं डी०पी०आर०/निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच/एकरारनामा में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 4 योजना पुनरीक्षण की प्रक्रिया में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' के रूप में संलग्न है।
- 27 का स्थल अप्राप्त है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'च' में द्रष्टव्य है।
- 25 योजनाओं का विभागीय पत्रांक 5669 दिनांक 15.06.2016 के द्वारा प्रशासी विभाग से अनुमोदित मॉडल नक्शा एवं प्राक्कलन की मांग की गई है, जो कि अप्राप्त है एवं इसकी विवरणी परिशिष्ट 'छ' पर है। विभाग द्वारा प्रखंड सूचना प्रौद्योगिक भवन के लिये प्रशासी विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शा पर विस्तृत प्राक्कलन गठित कर निविदा इत्यादि कार्रवाई दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹21600.00 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध ₹3065.86 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग-3 में कुल ₹4616.51 लाख का बजट उपबंध प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक आगणन से किया गया है।

DmC  
3550  
07.12.16

PMU  
K. Singh

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- दिनांक 22.08.2016 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ हुई बैठक के आलोक में सभी प्रतिस्थापित योजना (बेन को छोड़कर) एवं पूर्व स्वीकृत वैसी योजना जिसका अभी तक स्थल अप्राप्त है, को निरस्त किया जाय।
- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
- विभाग द्वारा विकसित PMIS पर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग भवन निर्माण के वेबसाईट पर जाकर आईडी-RDD एवं पासवर्ड-RDD का उपयोग कर विधिवत जानकारी लिया जा सकता है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-15/2016.....11844(ग)/पटना, दिनांक 7/12/16

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।